

# अब हरिद्वार से वाराणसी तक बढ़ेगा गंगा एक्सप्रेस-वे

एक्सप्रेस-वे को मेरठ से हरिद्वार और प्रयागराज से वाराणसी तक बढ़ाने की तैयारी, एक्सप्रेस-वे के विस्तार का प्रस्ताव तैयार कर रही सरकार

अधर उत्तराखण्ड चलूरी

सत्यानन्द। मेरठ से प्रयागराज तक बढ़ने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे को अब हरिद्वार से वाराणसी तक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तार मेरठ से हरिद्वार और प्रयागराज से वाराणसी तक करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युधिष्ठिर नाम के निर्देश दिये।



जान्दा लैसर करने के निर्देश दिये।

सरकार के प्रबन्धक ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्धारण के बाहर वाराणसी को एक्सप्रेस-वे बनाने की योजना को प्रभावी रूप से साझा किया जा रहा है। पूर्वोत्तर के जिलों का एनसीआर के साथ दिल्ली तक सड़क मार्ग में मीठा मंदसूख स्थापित होगा। इसमें कोलकाता से लैसर दिल्ली तक वाराणसी और प्रयागराज यांत्रिक प्रदेश की परियाहन यात्रियों को मजबूत किया जा सकेगा।

केंद्र सरकार के अन्त बजट में

गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तार के बाद इसकी लंबाई 150 किलोमीटर बढ़ जाएगी। यही अब एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई 745 किलोमीटर होगी। उन्होंने कहा कि प्रयागराज से वाराणसी तक के विस्तार में गंगा एक्सप्रेस-वे के अन्तर्गत भी यह रह रहा रहने वाला है।

**150 किलोमीटर  
जारी की जाएगी**

पूर्वोत्तर और उत्तर के कई जिलों में विकास की जारी रह रही है। गंगा एक्सप्रेस-वे वाराणसी के साथ मिर्जापुर, भटेही, सोनभद्र और चंटीली को भी जोड़ जाएगा। एक्सप्रेस-वे विस्तार के साथ ही इन क्षेत्रों में उन्होंने और पर्यटन के विकास के साथ रोजगार की संभवता भी बढ़ावी। उन्होंने कहा कि मौजूद समय में गंगा एक्सप्रेस-वे की लंबाई कुल 594 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। निर्माण की लागत 36,402 करोड़ रुपये तक हो रही है। गंगा एक्सप्रेस-वे मेरठ, हरिद्वार, असाम, संभल, राजगढ़पुर, हारलोड, उन्नाल और रामबरेली, प्रातामाड में होते हुए प्रयागराज तक जारी होंगे। गंगा एक्सप्रेस-वे विकास रोड का होगा। भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा।

बलिया तक होगा

पूर्वोत्तर एक्सप्रेस-वे का विस्तार

प्रदेश सरकार के प्रबन्धक ने कहा कि योगी सरकार पूर्वोत्तर एक्सप्रेस-वे की का विस्तार भी बलिया तक करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर एक्सप्रेस-वे को बलिया तक विस्तार देने का प्रस्ताव जान्दा रहिया करने के निर्देश दिये हैं। ताकि केंद्र सरकार से बदल ली जा सके।